रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1984/अग्रहायण 9, 1906
No. 174] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 1984/AGRAHAYANA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1984

संकल्प

सं. आर-43011/2/82/एल.डब्ल्यू .—पिछले कुछ समय से, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) को भवन तथा निर्माण उद्योग से अभिवेदन प्राप्त हो रहे है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाई गई तीन योजनाओं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाई गई योजना के उपबंधों का अनुपालन करने में उनके द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में हैं । सरकार ने इन अभिवेदनों पर उचित विचार करने के पश्चात् अब यह निर्णय लिया है कि एक त्रिपक्षीय कार्यकारी ग्रुप गठित किया जाए, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारी, उद्योग में नियोजकों के प्रतिनिधि और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों । इस त्रिपक्षीय समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

2. गठन :

केन्द्रीय सरकार

1. अपर सचिव, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग, नई दिल्ली। —अध्यक्ष
2. महानिदेशक (श्रम कल्याण), श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग, नई दिल्ली। —सदस्य सचिव
3. सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय, या उनका प्रतिनिधि । —सदस्य

4. सचिव, —सदस्य
रेलवे बोर्ड,
या उनका प्रतिनिधि ।

5. सचिव, —सदस्य
रक्षा मंत्रालय,
या उनका प्रतिनिधि ।

6. महा निदेशक, —सदस्य
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

7. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, —सदस्य
नई दिल्ली ।

राज्य सरकारें

8. कर्नाटक सरकार का एक
प्रतिनिधि —सदस्य

9. पश्चिम बंगाल सरकार
का प्रतिनिधि —सदस्य

10. दिल्ली प्रशासन का —सदस्य
एक प्रतिनिधि

11. गुजरात सरकार का
एक प्रतिनिधि । —सदस्य

12. मध्य प्रदेश सरकार का —सदस्य
एक प्रतिनिधि

नियोजकों के प्रतिनिधि

13. सेक्रेटरी, —सदस्य
इम्पलायर्स फेडरेशन आफ इंडिया,
बम्बई 1 ।

14. सेक्रेटरी, —सदस्य
अखिल भारतीय उत्पादक संगठन,
बम्बई ।

15. सेक्रेटरी, —सदस्य
स्टैन्डिंग कानफ्रैन्स आफ पब्लिक
इंटरप्राईजेज, नई दिल्ली ।

16. सेक्रेटरी, —सदस्य
अखिल भारतीय नियोजक संगठन,
नई दिल्ली ।

17. अध्यक्ष, —सदस्य
आल इंडिया ब्रिक एण्ड टाइल
मैनूफैक्चरर्स फेडरेशन, नई दिल्ली ।

ट्रेड यूनियन

18. जनरल सेक्रेटरी, —सदस्य
इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस
नई दिल्ली ।

19. जनरल सेक्रेटरी, —सदस्य
आल इंडिया ट्रेड यूनियन
कांग्रेस, नई दिल्ली ।

20. जनरल सेक्रेटरी, —सदस्य
भारतीय मजदूर संघ,
नई दिल्ली ।

21. जनरल सेक्रेटरी, —सदस्य
सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन,
नई दिल्ली ।

22. जनरल सेक्रेटरी, —सदस्य
हिन्द मजदूर सभा,
नई दिल्ली ।

3. इस त्रिपक्षीय समिति के विचारार्थ विषय निम्न लिखित होंगे :

(क) सामाजिक सुरक्षा कानून, अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और योजनाओं, उपदान संदाय अधिनियम, आदि का अनुपालन करने में सदन और निर्माण उद्योग द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाना; और

(ख) यह मालूम करना कि उपर्युक्त (क) में बताई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग में श्रमिकों के लिए किस प्रकार की विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए।

4. यह समिति अपने गठन की तारीख से 6 महीनों की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

लक्ष्मीधर मिश्रा,
महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 29th November 1984

RESOLUTION

No. R-43011/2/82-LW.—For sometime past the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) has been receiving representations from the Building and Construction Industry about the difficulties being faced by them in complying with the provisions of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the three Schemes framed thereunder, the Employees' State Insurance Act and the Scheme framed thereunder. The Government after due consideration of these representations have now decided to constitute a Tripartite Working Group consisting of the officials of the Central and

State Governments Employers, representatives in the Industry and the representatives of the Central Trade Union Organisations. The composition of the Tripartite Committee and the terms of reference will be as under :—

2. Compositon :

Central Government

1. Additional Secretary, Ministry of Labour & Rehabilitation Department of Labour New Delhi. —Chairman
2. Director General (Labour Welfare) Ministry of Labour & Rehabilitation Department of Labour, New Delhi. —Member Secretary
3. Secretary, Ministry of Works & Housing, or his representative. —Member
4. Secretary, Railway Board, or his representative. —Member
5. Secretary, Ministry of Defence, or his representative. —Member
6. Director General, Employees' State Insurance Corporation. —Member
7. Central Provident Fund Commissioner, New Delhi. —Member

State Governments

8. A representative of the Government of Karnataka —Member
9. A representative of the Government of West Bengal. —Member
10. A representative of the Delhi Administration —Member
11. A reprepsentative of the Government of Gujarat. —Member
12. A representative of the Government of Madhya Pradesh —Member

Employers' Representatives :—

13. The Secretary, Employers' Federation of India, Bombay-1. —Member
14. The Secretary, All India Manufacturers' Organisation, Bombay. —Member
15. The Secretary, Standing Conference of Public Enterprises, New Delhi. —Member
16. The Secretary, All India Organisation of Employers, New Delhi. —Member
17. The President, All India Brick & Tile Manufacturers' Federation, New Delhi. —Member

Trade Unions

18. The General Secretary, Indian National Trade Union Congress, New Delhi. —Member
19. The General Secretary, All India Trade Union Congress, New Delhi. —Member
20. The General Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangh, New Delhi. —Member
21. The General Secretary, Centre of Indian Trade Union, New Delhi. —Member
22. The General Secretary, Hind Mazdoor Sabha, New Delhi. —Member

3. The terms of reference of the Tripartite Committee would be as under :

(a) To identify the specific difficulties being faced by the Building and Construction Industry in complying with the social security legislation namely Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act and the schemes framed thereunder, the Employees' State Insurance Act and the schemes, the Payment of Grautity Act etc., and

(b) To work out what type of special social security cover should be formulated for the workers in the Industry keeping in view the difficulties as in (a) above.

4. The Committee will submit its report within a period of 6 months from the date of its constitution.

LAKSHMIDHAR MISHRA,
Director General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984